(ग) प्रशिक्षणाधीन विमान चालकों को भारत सरकार द्वारा कोई सहायतार्थ अनुदान नहीं दिया जाता । परन्तु वे प्रशिक्षणार्थी जिन्होंने मैट्रिक पास की होती है और जिनकी उम्र 28 साल से कम होती है वे सरकार से उपदान प्राप्त फ्लाइंग क्लबों में पहले वर्ष के दौरान 100 घंटे तक के लिये तथा प्रत्येक बाद के वर्ष में 50 घंटे तक के लिये बगैर उपदान की 75/- रुपये प्रति घंटा की दर के मुकाबले 10/- रुपये प्रति घंटा की रियायती दर पर उड़ान-कार्य कर सकते हैं । अन्य प्रशिक्षणार्थियों की हालत में, अर्थात् जो मैट्रिक पास नहीं होते अथवा जिनकी आयु 28 वर्ष से ऊपर होती है, उन्हें 25/- रुपये प्रति घंटा की दर से उड़ान-शुल्क देना पड़ता है ।

(घ) फिलहाल उपदानित दरों पर स्वीकृत उड़ान की मात्रा में कोई कमी करने का प्रस्ताव नहीं ।

Roads of Economic and Inter-State Importance in Madhya Pradesh

1627. **Shri Nathu Ram Ahirwar:**
Shri G. C. Dixit:
Shri Y. S. Kushwah:
Shri J. Sundar Lal:

Will the Minister of Transport and Shipping be pleased to state:

(a) whether any proposal has been sent by the Government of Madhya Pradesh for centrally financing of the construction of roads of economic and inter-State importance during the Fourth Five-Year Plan;

(b) if so, whether the proposals have been accepted and sanction has since been issued by Government; and

(c) if not, when the proposals are likely to be accepted?

The Minister of Transport and Shipping (Dr. V. K. R. V. Rao): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) A decision on the proposals can be taken only after the Fourth Plan allocations have been finalised.

Declaration of Roads as National Highways in Madhya Pradesh

1628. **Shri Nathu Ram Ahirwar:**
Shri G. C. Dixit:
Shri Y. S. Kushwah:
Shri J. Sundar Lal:

Will the Minister of Transport and Shipping be pleased to state:

(a) whether the Government of Madhya Pradesh have forwarded any proposal for declaration of certain roads in Madhya Prades as National Highways; and

(b) if so, whether the proposal has been accepted by Government?

The Minister of Transport and Shipping (Dr. V.K.R.V. Rao): (a) Yes, Sir.

(b) A decision on the proposals received for additions to the existing National Highway System in the Fourth Plan period can be taken only after the plan allocations have been finalised. Meanwhile, in order to examine the proposals, the State Governments concerned have been requested to supply essential technical data.

आम चुनावों पर खर्च

1629. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :** क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे आम चुनावों में मैसूर राज्य में कितना धन खर्च हुआ ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): जहां तक कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय साधारण निर्वाचनों के दौरान मैसूर राज्य में उपगत व्ययों का सम्बन्ध है, उनका वर्णन इन साधारण निर्वाचनों पर निर्वाचन आयोग की तत्सम्बन्धी रिपोर्टों में किया गया है भारत में प्रथम साधारण निर्वाचन, 1951-52